

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 08/2021 (राजस्व अपील)

RCMS NO : 2021/18

अनवान

1. श्री रता पिता श्री रामा कुमावत, निवासी सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

—अपीलान्त

बनाम

1. पटवारी पटवार हल्का सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपा पिता श्री अम्बावा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री नाथा पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हकरा पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री मानाराम पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री नाना पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अभिभाषक।

अपील अंतर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
अपील विरुद्ध प्र.सं. 4/2020 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, आदेश दिनांक 10.
03.2021

*** निर्णय ***

दिनांक – 23-02-2022

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1527, 1533, 2664/1529 भूमि स्थित है, जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1527, 1533, 2664/1529 हमारी खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलान्त द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसे हटाया जावे। उक्त



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार झाड़ोल को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पटवारी को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो अपीलान्त की अनुपस्थिति में बनायी जाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल ने मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा की आराजी संख्या 1533 पर अतिक्रमण के संबंध में अपीलान्त को तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर अपीलान्त ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 1533 रकबा 0.2700 हेक्टेयर पर अपीलान्त की अन्य आराजीयात के समीप स्थित है एवं उक्त भूमि पर अपीलान्त का आधिपत्य सेटलमेंट से पूर्व से चला आ रहा है। अपीलान्त की पक्की वाउण्डीवाल बनी होकर काश्त की जा रही हैं एवं अपीलान्त का ट्युबवेल होकर मौके पर उडद की फसल मौजूद है। अपीलान्त ने रेस्पोजेन्ट्स की भूमि पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अपीलान्त की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त द्वारा इनके विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखे है, जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के जवाब को पढ़े बिना एवं दस्तावेज, साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को यह ज्ञान होते हुए भी उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। मौके पर विधि विरुद्ध तरीके से अपीलान्त की बनी हुई वाउण्डीवाल को तोड़कर मौके की स्थिति को बदल दिया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री शिवकुमार सालवी अधिवक्ता द्वारा वकालातपत्र प्रस्तुत किया गया। शेष रेस्पोजेन्ट के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्त अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से कोई उपस्थित न होने से मामले में अपीलान्त अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्त अधिवक्ता ने अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी संख्या 1533 रकबा 0.2700 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा सेटलमेंट से पूर्व का होना, मौका रिपोर्ट एकतरफा होना, अपीलान्त की वाउण्डीवाल, ट्युबवेल होना, काश्त होना अवगत कराया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा 183-बी के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो विधिनुसार है।

हमने अपीलान्त अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्त की अपील, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता है कि रेस्पोजेन्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी भूमि में अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने से अपीलान्त को बेदखल करने का अनुरोध किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार झाड़ोल को प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण संख्या 04/2020 दर्ज कर अपीलान्त को नियमानुसार सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पुनः जांच बाबत अनुरोध करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में पुनः मौका जांच करायी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है।

मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलान्त अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है एवं रेस्पोजेन्ट्स अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य द्वारा बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा किया गया है। अपीलान्त द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रेस्पोजेन्ट्स के नाम दर्ज भूमि पर उसका कोई वैध अधिकार हो। अपीलान्त द्वारा कथित अतिक्रमित भूमि को उसकी खातेदारी भूमि के समीप होना अपील में बताया है, किन्तु स्वयं की खातेदारी भूमि के समीप अन्य वर्ग के सदस्य की भूमि होने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप किया जावे। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि बाबत वाद दायर करना अवगत कराया है, किन्तु पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज सलंगन नहीं किया है। अपीलान्त अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी की हैसियत से अपीलान्त का कथित भूमि पर कोई विधिक अधिकार सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183-बी में वर्णित प्रावधानानुसार प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर